Number of Villages and Harijan Bastis Electrified during Seventh Plan Period

*284. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what is the number of villages electrified during the Seventh Five Year Plan Period and the number of Harijan bastis electrified in the same period;

(b) whether Government are aware that electric supply to the rural areas is very faulty, irregular and meagre; and

(c) if so, what steps Government propose to take to streamline the rural electric supply network in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) During the Seventh Five Year Plan (*1985-90*), *1,00,506* villages and 1,00,740 Harijan Bastis approximately were electrified in the country.

The supply of power to rural areas from the State gride is managed by the State Electricity Boards who are also responsible for proper upkeep and maintenance of the system. The power cuts being imposed in certain rural areas are due to the overall shortage of power in the respective States and are decided by the States themselves. The deficiencies in distribution system, the maintenance of which is the responsibility of State Electricity Boards/States, are also, to some extent, responsible for faulty power supply.

For improving the rural distribution network, part of the funds for rural electrification allocated to various States by the Planning Commission are now being specifically earmarked for system improvement schemes, which includes setting up of new sub-stations, augmentation of the existing power lines, installation of capacitors, etc.

In addition, Power Finance Corporation also accords priority for funding system improvement schemes, and Renovation and Modernisation Schemes, which are intended to improve the overall power supply position.

श्री शांति त्यागी : उपसभापति महोदया, मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 7वीं योजना में हरिजन बस्तियों की संख्या 24,00,600 है जबकि माननीय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें हरिजन बस्तियों की तादाद जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है वह एक लाख से ऊपर है। यह बहुत बड़ा फर्क है आप कृपया इसको चेक अप करें।

सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यह है कि देश के जो बाकी एक लाख गांव बच गये हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची है आप कृपा करके बतायें कि उन बाकी गावों में कब तक आप और राज्य सरकारें मिल कर बिजली पहुंचाने की कृपा करेंगे, नम्बर एक। इसी में दूसरा है जैसे उत्तर प्रदेश में पिछले साल से ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम बिल्कुल चौपट पड़ा हुआ है क्या मंत्री जी को यह जानकारी है और अगर है तो क्या मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह देंगे कि भले आदमियों आप कम से कम इस ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना को, जब पैसा भी ऊपर से मिल रहा है तो चालू करो। मेरे यह दो सप्लीमेंट्रीज है। बढ़िया से जवाब दीजिए।

श्री कल्पनाथ राय : मैडम डिप्टी चेयरमैन, ग्रामीण विद्युतीकरण के माध्यम से हिंदुस्तान के गांवों का विद्युतीकरण होता है और पूरे देश में 5,89,000 गांव हैं जिसमें से 92 हजार गांवों का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है। जिन राज्यों में ज्यादा विद्युतीकरण नहीं हुआ है उसमें

यू. पी. के 72,000 गांव हैं, बिहार के 20,000 गांव हैं, उड़ीसा के 14,000 गांव हैं, बंगाल के 1,0000 गांव हैं और मध्य प्रदेश के 8,000 गांव है। उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 1990–91 में जो रुपया दिया गया था वह 2,550 गांवों के विद्युतीकरण के लिए दिया गया था और उन्होंने केवल 2,200 गांवों का विद्युतीकरण किया। 1991–92 में उन्हें 1,550 गांवों का विद्युतीकरण करना था मगर उन्होंने केवल 702 गांवों का किया। आदरणीय डिप्टी चेयरमैन महोदया, आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय दूसरे काम में लीन है। इसलिए उसके पास विद्युतीकरण के संबंध में अभी काम करने के लिए समय नहीं है। मैं उस सरकार से अपने आदरणीय मंत्रियों और संसद सदस्यों के माध्यम से यह प्रार्थना करूंगा कि.. (व्यवधान)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Madam, it is irrelevant.

SHRI S. JAIPAL REDDY: We would like to state that the reply of the Minister is irrelevant...(Interruptions) You will kindly appreciate that the reply of the Minister is not relevant.

उपसभापति : मंत्री जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : .. (**व्यवधान**) बार बार अयोध्या का उल्लेख हो तो यह इनके मन में छुपे डर का ही प्रदर्शन है। किसी भी विषय में आप अयोध्या को जरूर लाइये (**व्यवधान**) बहुत अच्छा है (**व्यवधान**)

श्री कल्पनाथ राय : मैडम डिप्टी चेयरमैन, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही मैंने यह कहा है ...

उपसभापति :

I am not permitting any cross-talk, please.

मंत्री जी आप अपना जवाब दीजिए।

श्री कल्पनाथ राय : मैंने आपसे सिर्फ यह कहा है कि 1991–92 में 1,550 गांवों का प्लानिंग कमीशन और आर.ई.सी. के माध्यम से विद्युतीकरण उत्तर प्रदेश में होना था मगर केवल 702 गांवों में हुआ है और जो रुपया उनको दिया गया था उस रुपए का पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को लिखूंगा कि जो टारगेट प्लानिंग कमीशन में तय हुआ है उस टारगेट को पूरा करें। (**व्यवधान**)

श्री शांति त्यागी : गांवों में बजली के तार खींचकर और खम्बे गाड़ कर खाली प्रसन्न मत हो जाइये। कृपा करके यह बताये कि जहां बिजली के खम्भे लग गये हैं वहां गांव वालों को 18 घंटे पावर और रोशनी की व्यवस्था आप कब तक करेंगे?

श्री कल्पनाथ राय : मैडम डिप्टी चेयरमैन, विद्युतीकरण एक कान्कारेंट सबजैक्ट है। विद्युत को गांवों तक पहुचाने और रेगुलेट करने का काम स्टेट सरकार का है। 25 परसैंट पावर सेक्टर जनरेशन सेन्ट्रल सेक्टर में होता है और 75 फीसदी स्टेट सेक्टर में आता है। यह एवजीक्यूटिव रिस्पांसिबिलिटी स्टेट सरकार की है कि वह कितने गांवों का विद्युतीकरण करती है, कितनी हरिजन बस्तियों का करती है, कितनी और बस्तियों का करती है, कितना सप्लाई करती है, कहां पावर कट करती है। यह जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। मैं आपकी भावनाओं से प्रदेश सरकार को अवगत करा दूंगा।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उपसभापति, महोदया, माननीय मंत्री महोदय को मालूम होगा कि जितनी स्कीम्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की हैं, वह केन्द्र द्वारा स्वीकार की जाती हैं जिन्हें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड या कार्पोरेशन स्वीकार करता है। मेरी जानकारी है कि यह संख्या बढ़ चढ़ाकर 100506 दी गयी है, सामान्यतः रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड हमेशा इनमें घांधली करता रहा है। जो आन गोइंग स्कीम है उनको भी और जो बंद हो गयी हैं उनको भी शामिल संख्या किया जाता रहा है और क्या मंत्रीजी को जानकारी है कि इ

प्रकार की शिकायतें लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के जो चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ लगाए गए हैं ? क्या आपको इन आरोपों के बारे में मालूम है और मालूम है तो क्या आप जांच कराएंगे ?

श्री कल्पनाथ राय : मैडम डिप्टी चेयरमैन, यह सवाल ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन के संबंध में ही बता रहा हूं

उपसभापति : सुनें तो, आगे बोलने तो दीजिए जुमला ।

श्री कल्पनाथ राय : मैडम डिप्टी चेयरमैन, ग्रामीण विद्युतीकरण एक फायनेंसियल एजेंसी जोकि योजना आयोग द्वारा प्रदेश के गांवों के विद्युतीकरण के लिए जो प्लान आउटले होता है और उसके अलावा आर०ई०सी० से फायनेंस होती है । इस योजना को श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन् 69 में शुरू किया था । उसमें प्लान एलोकेशन के अनुरूप उनको पैसे दिए जाते हैं । तो उन राज्यों की क्या धांधली होती है, क्या नहीं होती है, यह सवाल स्टेट का है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह रिमार्क्स जो आपने दिए हैं, ये उसी कार्पोरेशन के दिए हुए हैं ।

उपसभापति : माथुर साहब आपने सवाल पूछ लिया... **(व्यवधान)**... माथुर साहब, आप बार-बार नहीं उठिए, यह आपको शोभा नहीं देता ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : चेयरमैन के खिलाफ जो आरोप हैं, क्या आप उनकी जांच कराएंगे ?

श्री कल्पनाथ राय : मैडम डिप्टी चेयरमैन, जो सवाल माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, इसके लिए मुझे सेपरेट नोटिस चाहिए । इस संबंध में अभी जवाब नहीं दे सकता ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : स्वयं आपको चिट्ठी बता दूं मैं आपको कि किस-किस तरह के आरोप हैं । आपको मालूम है ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us cover more questions. I would be happy if we cover more questions... (Interruptions)... Let us cover more questions. Question No. 285.

श्री मूलचन्द मीणा : मैडम, आपक संरक्षण चाहता हूं ।

उपसभापति : नहीं नहीं, वह सवाल आगे बढ़ गया । मीणा जी, आप नए मेंबर हैं । मैं आप जैसे मेंबर्स के लिए एक लिबर्टि लेना चाहूंगा कि 20 क्युश्चंस आते है बैलेट में और अगर हम जल्दी जल्दी करें तो हो सकता है कि आगे के क्युश्चंस में आप सवाल पूछ सकें और मंत्रीजी उनके जवाब दे सकें । बैठिए ।

I have already called Question No. 285...(Interruptions)...That has gone. Somebody should explain to him that I have moved to another question.

श्री रजनी रंजन साहू : मैडम इतनी सप्लीमेंटरीज का सिस्टम बंद होना चाहिए ।

उपसभापति : बहुत ज्यादा सप्लीमेंटरीज होती हैं । एक प्रश्न में 25-25 सप्लीमेंटरीज नहीं चलेंगी ।

श्री मूलचन्द मीणा : चर्चा के लिए रखलें, आधे घंटे की चर्चा के लिए रखलें आगे से ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will do that...(Interruptions)...

Agreement between Air India and U.S. Exim Bank

*285. DR. ABRAR AHMED:
SHRI SURESH KALMADI:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

---

†The question was acutally asked on the floor of the Houe by Shri Sukomal Sen.